अनुदान संख्या 30 – व्यय विभाग
GRANT No. 30 - DEPARTMENT OF EXPENDITURE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	413,33,00	413,34,00	288,60,65	-124,73,35
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				123,02,32

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय– सामान्य सेवाएं	Secretariat- General Services				
मू.	O.	12323.00	13268.30	13099.63	-168.67
पु.	R.	945.30			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	24000.00			
पू.	S.	1.00	10716.93	10746.50	+29.57
पु.	R.	-13284.07			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3475" – "अन्य व्यय – लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली" के अंतर्गत ₹13254.50 लाख की बचत (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹24001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम परामर्शदाताओं को रखे जाने, आउटसोर्स स्टॉफ, रिक्त पदों को न भरें जाने, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की खरीद को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – व्यय विभाग" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹776.63 लाख का अधिक व्यय (₹12323.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बकाया वेतन, मानदेय, लंबित बिलों की मंजूरी होने एवं जनशक्ति की आउटर्सोसिंग संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) Under Major Head "3475" – "Other Expenditure - Public Financial Management System" - saving of ₹13254.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹24001.00 lakhs including supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2018) was due to hiring of less consultants, outsourced staff, non-filling up of vacant posts and non-materialization of proposals for procurement of software and hardware.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Expenditure" - excess of ₹776.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12323.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary arrears, honorarium, clearance of pending bills and outsourcing of man power.